A fact-finding inquiry however, was made into the following three specific items brought out in the report of the Bosu Committee:—

(i) Non-accounting of skins of 103 dead animals;

(ii) Death of 22 crossbreed rams after dipping in garrathion solution for treatment of mange; and

(iii) Treatment of sick animals.

As a result of the inquiry, disciplinary proceedings were initiated against four scientists for their administrative and technical lapses and appropriate action was taken against them.

(c) The then Director of the C.S. & W.R.I. Avikanagar was appointed at the ICAR headquarters in June, 1981 keeping in view all the circumstances of the case. The appointment was made subject to the disciplinary action that might become necessary in the light of the Inquiry Committee's findings.

(d) No further action is now called for as appropriate action has already been taken.

देश में चीनी मिलों द्वारा गन्नों की बकाया राशि का भुगतान

2851. **श्री सोहन लाल धूसिया :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खलीलाबाद, मुंडेरवा, बस्ती गोविन्द नगर और बभनन स्थित चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों की कितनी राशि बकाया है और यह राशि कब से बकाया है ;

(ख) क्या चीनी मिलों की ओर बकाया राशि पर किसानों को ब्याज मिलने की सभावना है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि मिल-मालिकों द्वारा किसानों को देय बकाया राशियों का मसला शीघ्र हल हो जाये ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश की खलीलाबाद, मुंडेरवा, बस्ती और बभनान चीनी फैक्ट्रियों के बारे में 30-6-85 को गन्ने के भुगतान की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(आंकडे लाख रुपयो मे)

चीनी फैक्ट्री	1984–85 मौसम के लिए देय गन्ने का कुल मूल्य	गन्ने का अदा किया गया मूल्य	1984–85 मौसम के लिए शेष राशि	1983–84 और पिछले मौसमों के लिए बकाया राशि
खलीलाबाद	42.95	13.67	29.28	शून्य
मुंडेरवा	65.25	52.73	12.52	शून्य
बस्ती	106.96	106.96	शून्य	शून्य
बभनान	82.80	55.69	27.11	0.11

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबन्धों के अनुसार, गन्ने को सुपुर्द करने की तारीख के 14 दिनों के बाद बिना अदा किए गए गन्ने के मूल्य की शेष रह गई राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज देय होता है।

(ग) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि और विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का भुगतान करवाने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अपेक्षित फील्ड संगठन होते हैं। केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करवाने के लिए उद्योग की तरलता स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाती आ रही है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति पर नजर रख रही है और उनका शीघ्र भुगतान करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों को निदेश जारी करती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यनिष्पादन काफी संतोषजनक रहा है जैसाकि इस तथ्य से विदित होगा कि उत्तर प्रदेश में 1984-85 मौसम के लिए 30-6-85 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि गन्ने के कुल मूल्य का 6.2 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी तारीख को वह 20.8 प्रतिशत थी।

Disposal of imported sugar by FCI

2852. SHRI K. VASUDEVA PANICKER:
SHRI J. P. GOYAL:
SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the procedure followed by Government for disposal of imported sugar by the Food Corporation of India;

(b) whether Government have received complaints regarding non-adherence to procedures by FCI in regard to dilevery of imported sugar;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government to streamline the functioning of FCI and ensure proper disposal of imported sugar?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) The scheme for disribution of imported sugar has come into operation from June, 1985. Under the scheme the Statewise quota of imported sugar have been fixed and allotted to various State Governments for lifting of imported sugar from the Food Corporation of India and for eventual sale through the controlled channels in freesale to the consumers at a issue price of less than Rs. 6 per kg. This issue price has now been reduced to Rs. 5.80 per kg. Food Corporation of Indai is also arranging the sale of imported sugar through auction/tenders at selected centres.

Besides the allocation of imported sugar meant for freesale distribution, certain quantity of imported sugar is also allotted to State Governments as levy sugar for distribution through the public distribution system.

(b) No, Sir. Food Corporation of India is arranging the delivery of imported sugar to State Governments for distribution through controlled channels and sale of imported sugar through auction/ tenders as per the guidelines issued by the Government from time to time

(c) and (d) Do not arise.

Smaller flats by DDA

2853. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Governbent's consideration for construction of smaller flats by DDA;